Weekly One Liners 12th to 18th May, 2025

राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया

एक दुर्लभ संवैधानिक कदम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 का हवाला देते हुए अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधान के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों और आचरण से संबंधित कई कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय मांगी है। राष्ट्रपति का यह संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले से उपजा है जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा की गई देरी की आलोचना की गई है।

समाचार में क्यों?

13 मई 2025 को राष्ट्रपति **द्रौपदी मुर्मू** ने भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 143** के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है। यह सलाह राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका से जुड़े 14 संवैधानिक प्रश्नों पर आधारित है। यह कदम **तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय में देरी** को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए **8 अप्रैल 2025** के फैसले के बाद उठाया गया।

राष्ट्रपति संदर्भ के तहत उठाए गए प्रमुख प्रश्न

1. जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास कौन-कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं?
2. क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होना चाहिए?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा किए गए विवेकाधीन निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं?
4. क्या अनुच्छेद 361 (राष्ट्रपति/राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से छूट) न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः रोक प्रदान करता है?
5. यदि संविधान राज्यपाल के विवेकाधीन निर्णय की समय-सीमा या प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, तो क्या न्यायालय समय-सीमा और प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है?
6. क्या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के तहत लिए गए निर्णय न्यायिक जांच के अधीन हैं?
7. क्या न्यायिक आदेश राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे और कब करना है, यह निर्देशित कर सकते हैं?
8. जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना आवश्यक होता है?
9. क्या विधेयक के कानून बनने से पहले ही उसके विषय-वस्तु पर न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है?
10. क्या न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को प्रतिस्थापित कर सकता है?
11. क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी "प्रचलित कानून" माना जा सकता है?
12. क्या सुप्रीम कोर्ट की पीठ को संविधान की व्याख्या संबंधी मामलों को कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजना अनिवार्य है (अनुच्छेद 145(3))?
13. क्या अनुच्छेद 142 केवल प्रक्रिया संबंधी कानूनों तक सीमित है या यह मौलिक संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध निर्देश देने की शक्ति भी देता है?
14. क्या केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा केवल अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल वाद द्वारा ही हो सकता है?

पृष्ठभूमि और कारण

- तमिलनाडु सरकार ने एक याचिका दायर कर राज्यपाल **आर.एन. रवि** द्वारा **10 दोबारा पारित विधेयकों** पर कार्रवाई में देरी को चुनौती दी थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की निष्क्रियता को असंवैधानिक करार दिया और माना कि विधेयकों को **मौन स्वीकृति** मिल गई है।
- इस निर्णय ने **न्यायिक सक्रियता और कार्यपालिका की सीमा** को लेकर संवैधानिक बहस छेड़ दी, जिससे राष्ट्रपति को यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ा।

सांविधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 200	राज्यपाल के पास राज्य विधेयकों पर स्वीकृति, अस्वीकृति या राष्ट्रपति के पास भेजने के विकल्प
अनुच्छेद 201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की भूमिका
अनुच्छेद 143	राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार
अनुच्छेद 142	सुप्रीम कोर्ट को "पूर्ण न्याय" करने की शक्ति
अनुच्छेद 145(3)	संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनने की व्यवस्था
अनुच्छेद 361	राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्यवाही से छूट

इस संदर्भ का महत्व

- राष्ट्रपति और राज्यपाल की **विधायी प्रक्रिया में भूमिका स्पष्ट** करने में मदद करेगा।
- विधेयकों की स्वीकृति को लेकर **समयबद्धता तय हो सकती है**, जिससे विधायी जड़ता रोकी जा सके।
- **कार्यपालिका और न्यायपालिका** के बीच शक्ति संतुलन पर निर्णय तय करेगा।
- यह फैसला **संघीय ढांचे** और **केंद्र-राज्य संबंधों** को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।

भारत और EU के बीच एफटीए वार्ता आज से होगी शुरू

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है, जिसका 11वां दौर 12 मई 2025 से ब्रसेल्स में शुरू हुआ है। यह दौर समझौते के अंतरिम चरण को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो दो-चरणीय समझौता ढांचे का हिस्सा है और वर्ष के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल भारत की व्यापारिक कूटनीति में हालिया प्रगति के बाद आई है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ FTA लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है।

समाचार में क्यों?

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ताएं एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। दोनों पक्षों ने दो-चरणीय समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है। यह भारत द्वारा वर्ष 2025 में प्रमुख व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने की नई रणनीति का हिस्सा है, जिनमें यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही वार्ताएं भी शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की ब्रसेल्स यात्रा इस बात को रेखांकित करती है कि भारत यूरोप में व्यापारिक बाधाओं को कम कर बाजार तक पहुंच बढ़ाने को लेकर गंभीर है, विशेषकर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच।

प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य

- अंतरिम समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना।
- वर्ष 2025 के अंत तक व्यापक FTA को पूर्ण करना।
- बाजार पहुंच बढ़ाना और गैर-शुल्कीय बाधाओं (NTBs) को कम करना।
- कम संघर्ष वाले क्षेत्रों में व्यापार उदारीकरण से शुरुआत करना।
- हाल ही में संपन्न व्यापार समझौतों (यूके, ऑस्ट्रेलिया) की गति को बनाए रखना।

पृष्ठभूमि और स्थायी जानकारी

- भारत-ईयू FTA वार्ताएं कई चरणों में चल रही हैं; वर्तमान में 11वां दौर 12–16 मई, 2025 तक ब्रसेल्स में आयोजित हो रहा है।
- भारत ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीमित आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) पर हस्ताक्षर किए थे।
- भारत-यूके FTA वार्ताएं भी महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँच चुकी हैं।
- भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की संभावनाएं भी तलाश रहा है।
- यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, और यह FTA भारत के वस्त्र, आईटी, दवाओं और ऑटोमोबाइल जैसे निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित हो सकता है।

समझौते का महत्त्व

- भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक एकीकरण को और गहरा करेगा।
- तेज़ी से आगे बढ़ती बातचीत भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाती है कि वह 2025 में अनेक FTA सुनिश्चित करना चाहता है।
- ट्रंप-युग की संरक्षणवादी नीतियों और वैश्विक व्यापार अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करता है।
- पारस्परिक निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और व्यापार पर सामरिक तालमेल को प्रोत्साहित करता है।
- भारत की वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में विश्वसनीय छवि को और सुदृढ़ करता है।

CAQM ने उत्तर भारत में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए नए निर्देश जारी किए

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण से निपटने की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में लिया गया है और इसका उद्देश्य धान की कटाई के मौसम में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।

क्यों चर्चा में?

- CAQM के ये निर्देश इस कारण से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पराली जलाना उत्तर भारत में खासकर सर्दियों के दौरान गंभीर वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। दिल्ली-NCR की हवा हर साल खराब होती जा रही है, और इन निर्देशों के माध्यम से टिकाऊ व निवारक कृषि उपायों को संस्थागत रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

CAQM के प्रमुख निर्देश

1. समर्पित "पराली संरक्षण बल" का गठन:
- पुलिस अधिकारियों और कृषि विभाग के कर्मियों को शामिल कर निगरानी व प्रवर्तन सुनिश्चित करना।

2. ईंट भट्टों में धान के भूसे से बने पैलेट/ब्रिकेट्स का अनिवार्य उपयोग:
- जैसे थर्मल पावर प्लांट में को-फायरिंग में उपयोग किया जाता है, वैसे ही कच्ची पराली जलाने से बचाव।

3. प्रत्येक खेत की मैपिंग:
- यह निर्धारित करने के लिए कि कहाँ इन-सीटू (फील्ड में ही प्रबंधन) या एक्स-सीटू (फील्ड के बाहर उपयोग) उपाय लागू किए जा सकते हैं; साथ ही फसल विविधिकरण को भी बढ़ावा देना।

4. धान के भूसे के लिए सामान्य खरीद दर तय करना:
- पंजाब और यूपी को हरियाणा के मॉडल के अनुसार भूसे की खरीद के लिए एकसमान दर तय करनी होगी ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिल सके।

5. एक्स-सीटू प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना:
- बेलर, रेकर और अन्य मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि फसल अवशेष को हटाकर उसका पुनः उपयोग किया जा सके।

6. तकनीकी एकीकरण:
- पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक रियल-टाइम डेटा प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना।

7. फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों की सूची की समीक्षा:
- राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास उपलब्ध मशीनरी का सटीक मूल्यांकन हो और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग हो।

भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 पर बनी हुई है: 2021 एसआरएस रिपोर्ट

भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2021 में 2.0 रही, जो कि 2020 के समान है। यह जानकारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 में दी गई है। यह रिपोर्ट देश की बदलती जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों जैसे कि प्रजनन दर, वृद्ध होती जनसंख्या और विवाह रुझानों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार ने सबसे अधिक TFR 3.0 दर्ज की, जबकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम TFR 1.4 दर्ज की गई।

क्यों चर्चा में है?

भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) वर्ष 2021 में 2.0 रही, जो कि 2020 के समान है। यह जानकारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 7 मई 2025 को जारी की गई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 में सामने आई है। यह रिपोर्ट जनसंख्या वृद्धि, वृद्धावस्था, और विवाह रुझानों जैसी प्रमुख जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों की जानकारी देती है — विशेष रूप से तब जब 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है।

प्रमुख बिंदु: SRS 2021 रिपोर्ट के अनुसार

कुल प्रजनन दर (TFR)

- **राष्ट्रीय औसत:** 2.0 (2020 के समान)
- **सबसे अधिक TFR:** बिहार - 3.0
- **सबसे कम TFR:** दिल्ली व पश्चिम बंगाल - 1.4

TFR प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम:

- तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि

TFR प्रतिस्थापन स्तर या अधिक:

- असम (2.1), गुजरात (2.0), हरियाणा (2.0)

आयु संरचना में बदलाव

- **0–14 वर्ष की आबादी में गिरावट:**
- 1971 में 41.2% से घटकर 2021 में 24.8%
- **15–59 वर्ष (कार्यशील आयु वर्ग) में वृद्धि:**
- 53.4% से बढ़कर 66.2%
- **60+ वर्ष की वृद्ध आबादी:**
- 6% से बढ़कर 9%
- **65+ वर्ष:** 5.3% से बढ़कर 5.9%

वृद्ध आबादी राज्यों में:

- **सबसे अधिक वृद्धजन प्रतिशत:**
  - केरल: 14.4%
  - तमिलनाडु: 12.9%
  - हिमाचल प्रदेश: 12.3%
- **सबसे कम वृद्धजन प्रतिशत:**
  - बिहार: 6.9%
  - असम: 7%
  - दिल्ली: 7.1%

विवाह प्रवृत्तियाँ

- **महिलाओं की औसत विवाह आयु:**
  - 1990 में 19.3 वर्ष से बढ़कर 2021 में 22.5 वर्ष

SRS सर्वेक्षण के बारे में

- **कौन करता है:** भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संचालित
- **जनगणना के बाद सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण**
- **कवरेज:** 8,842 सैंपल इकाइयाँ
- **नमूना जनसंख्या:** लगभग 84 लाख लोग

निष्कर्ष:

SRS 2021 रिपोर्ट भारत की जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) की दिशा को दर्शाती है, जिसमें प्रजनन दर में गिरावट, वृद्धावस्था में वृद्धि और विवाह आयु में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण संकेत शामिल हैं। यह नीति निर्धारण और जनसंख्या से जुड़ी योजनाओं के लिए अहम दस्तावेज है।

अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में पहले 3एनएम सेमीकंडक्टर डिज़ाइन हब का उद्घाटन किया

केंद्रीय मंत्री **श्री अश्विनी वैष्णव** ने भारत के पहले **3 नैनोमीटर (nm) चिप डिज़ाइन केंद्रों** का नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक केंद्र **रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (Renesas Electronics India)** द्वारा स्थापित किए गए हैं और यह भारत की सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षमताओं में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक हैं। यह **आत्मनिर्भर भारत मिशन** के तहत भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

समाचार में क्यों?

भारत ने सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। पहली बार देश में 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित चिप डिज़ाइन केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत संकेत है।

मुख्य उद्देश्य और प्रमुख बिंदु

- **3nm चिप डिज़ाइन केंद्रों का शुभारंभ:** नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया।
- **भारत में अपनी तरह के पहले केंद्र:** ये केंद्र देश में पहली बार 3nm तकनीक पर चिप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो 5nm और 7nm डिज़ाइनों से एक बड़ा तकनीकी सुधार है।
- **रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा स्थापित:** यह एक वैश्विक अग्रणी एम्बेडेड सेमीकंडक्टर समाधान प्रदाता है।

सरकार की सेमीकंडक्टर रणनीति

- **समग्र रणनीति:** डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, एटीएमपी (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग) और सप्लाई चेन विकास को एकीकृत रूप में बढ़ावा।
- **वैश्विक समर्थन:** Applied Materials और Lam Research जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का समर्थन।
- **शैक्षणिक संस्थानों का योगदान:** 270+ से अधिक संस्थानों को EDA सॉफ़्टवेयर टूल्स दिए गए हैं; अब उन्हें सेमीकंडक्टर लर्निंग किट भी दी जाएंगी।
- **कौशल विकास:** उद्योग-तैयार इंजीनियरों के निर्माण हेतु नई सेमीकंडक्टर लर्निंग किट का शुभारंभ।

रणनीतिक महत्व

- **भू-राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण:** यह केंद्र भारत की रणनीतिक जरूरतों और भारत-जापान सहयोग को भी मजबूती प्रदान करते हैं।
- **सतत विकास:** यह पहल स्मार्टफोन, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल, रक्षा आदि क्षेत्रों के लिए आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेगी।

रेनेसास की भूमिका और दृष्टिकोण

- **वैश्विक विशेषज्ञता:** रेनेसास एम्बेडेड सिस्टम्स और सिस्टम-स्तरीय नवाचार में विशेषज्ञ है।
- **भारत के लिए रणनीति:** डिज़ाइन से लेकर परीक्षण तक की क्षमताओं को भारत में विस्तारित करने की योजना।
- **शिक्षा और स्टार्टअप के साथ साझेदारी:** Design Linked Incentive (DLI) और Chips to Startup (C2S) जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहयोग।

कैबिनेट ने जेवर में 3,706 करोड़ रुपये के एचसीएल-फॉक्सकॉन चिप प्लांट को मंजूरी दी

सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम (JV) को उत्तर प्रदेश के जेवर में एक सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने के लिए ₹3,706 करोड़ की मंजूरी दी है। यह भारत के ₹76,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठा प्रोजेक्ट है और उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला संयंत्र होगा। इसका उत्पादन 2027 में शुरू होने की उम्मीद है और यह लगभग **2,000 नौकरियाँ** पैदा करेगा और भारत की **40% चिप मांग** को पूरा करने में योगदान देगा।

क्यों चर्चा में?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक नए प्लांट को मंजूरी दी है। यह **HCL और Foxconn** का संयुक्त उपक्रम है जो **चिप असेंबली और पैकेजिंग** पर केंद्रित है। संयंत्र **उत्तर प्रदेश के जेवर** में स्थापित होगा और 2027 से कार्य करना शुरू करेगा।

उद्देश्य और लक्ष्य

- भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत असेंबली और परीक्षण यूनिट की स्थापना
- **घरेलू मांग का 40%** तक स्थानीय स्तर पर पूरा करके आयात पर निर्भरता घटाना
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में **आत्मनिर्भर भारत** को बढ़ावा देना
- उत्तर प्रदेश में **औद्योगिक आधारभूत ढांचे** और **रोजगार** का सृजन

प्रमुख विशेषताएं

बिंदु	विवरण
कुल निवेश	₹3,706 करोड़ (सरकारी प्रोत्साहन ₹1,500 करोड़)
संयंत्र प्रकार	फोन, लैपटॉप, कार व पीसी के लिए **डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स** की असेंबली और पैकेजिंग
क्षमता	प्रति माह 20,000 वेफर; 3.6 करोड़ यूनिट उत्पादन
स्थान	जेवर एयरपोर्ट के पास, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश
संभावित रोजगार	2,000 प्रत्यक्ष नौकरियाँ
उत्पादन प्रारंभ	वर्ष 2027 से

पृष्ठभूमि और संदर्भ

- **Foxconn का दूसरा प्रयास**: इससे पहले Vedanta के साथ JV 2023 में तकनीकी साझेदार की कमी के चलते विफल हो गया था।
- यह संयंत्र **भारत सेमीकंडक्टर मिशन** (2021 में $10 बिलियन के प्रारंभिक बजट के साथ शुरू हुआ) का प्रमुख हिस्सा है।
- अब तक भारत में **$18 अरब से अधिक का निवेश** आकर्षित हुआ है – प्रमुख कंपनियों में **Tata-PSMC, Micron, Kaynes, और CG Power-Renesas** शामिल हैं।
- भारत में **पहली मेड-इन-इंडिया चिप्स 2025 के अंत तक** आने की उम्मीद है।

महत्व

- भारत की सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूती देता है
- **मेक इन इंडिया** और **डिजिटल इंडिया** लक्ष्यों का समर्थन करता है
- **स्थानीय रोजगार** और **उत्तर प्रदेश को विनिर्माण हब** बनाने में मदद करता है
- भारत की **रणनीतिक स्वायत्तता** को बढ़ाता है, खासकर महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में

National Affairs

- एक दुर्लभ संवैधानिक कदम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 का हवाला देते हुए अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधान के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों और आचरण से संबंधित कई कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय मांगी है। राष्ट्रपति का यह संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले से उपजा है जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा की गई देरी की आलोचना की गई है। (Click here to read article)
- राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़े कदम के तहत, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने मेसर्स सेलेबी और उसकी सहयोगी कंपनियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा घोषित यह निर्णय सरकार के इस दृढ़ रुख को दर्शाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सभी अन्य बातों से ऊपर हैं। (Click here to read article)
- भारतीय खेल और रक्षा क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारतीय एथलेटिक्स में उनके अपार योगदान और हरियाणा के एक गांव से राष्ट्रीय नायक बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा को मान्यता देता है। (Click here to read article)
- भारतीय खेल और रक्षा क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारतीय एथलेटिक्स में उनके अपार योगदान और हरियाणा के एक गांव से राष्ट्रीय नायक बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा को मान्यता देता है। (Click here to read article)

- भारत ने मालदीव को $50 मिलियन की ट्रेज़री बिल सहायता एक साल के लिए और बढ़ाई, जिससे भारत की अपने पड़ोसी देशों के प्रति प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान की पुष्टि होती है। यह निर्णय मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के माध्यम से किया गया, ऐसे समय में जब द्वीपीय राष्ट्र गंभीर ऋण संकट और कूटनीतिक तनावों से जूझ रहा है। (Click here to read article)
- भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2024–25 के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) के चावल का अतिरिक्त 28 लाख टन आवंटन एथेनॉल उत्पादन हेतु मंज़ूर किया है। इससे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत कुल चावल आवंटन बढ़कर 52 लाख टन हो गया है। यह निर्णय भारत के 2025–26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में लिया गया है, हालांकि इससे खाद्य सुरक्षा और अनाज के ईंधन के रूप में उपयोग को लेकर बहस फिर से तेज़ हो गई है। (Click here to read article)
- सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम (JV) को उत्तर प्रदेश के जेवर में एक सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने के लिए ₹3,706 करोड़ की मंजूरी दी है। यह भारत के ₹76,000 करोड़ के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठा प्रोजेक्ट है और उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला संयंत्र होगा। इसका उत्पादन 2027 में शुरू होने की उम्मीद है और यह लगभग 2,000 नौकरियाँ पैदा करेगा और भारत की 40% चिप मांग को पूरा करने में योगदान देगा। (Click here to read article)
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण से निपटने की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में लिया गया है और इसका उद्देश्य धान की कटाई के मौसम में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। (Click here to read article)
- भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता प्रयासों के बाद पूर्ण और तात्कालिक युद्धविराम पर सहमति जताई है। यह घोषणा उस समय सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social पर एक पोस्ट साझा कर दोनों देशों को "सामान्य बुद्धि और अत्यंत समझदारी" दिखाने के लिए बधाई दी। इस निर्णय की पुष्टि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की, जिन्होंने बताया कि यह युद्धविराम 10 मई, 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से प्रभावी होगा। यह समझौता हाल के दिनों में बढ़े सीमा-पार तनाव और संघर्षों के बीच एक महत्वपूर्ण विराम के रूप में देखा जा रहा है। (Click here to read article)

States in the News

- 12 साल के इंतजार के बाद उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव के केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ शुरू हो गया है। प्राचीन वैष्णव परंपराओं में निहित यह आयोजन बृहस्पति ग्रह के मिथुन राशि में प्रवेश के साथ मेल खाता है, जो एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। हजारों भक्त, विशेष रूप से दक्षिण भारत से, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और आशीर्वाद के लिए अलकनंदा और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर एकत्र हुए हैं। (Click here to read article)
- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ी गति देते हुए, ReNew Power ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के बेथपल्ले गाँव में देश के सबसे बड़े एकल-स्थल नवीकरणीय ऊर्जा (RE) परिसर की स्थापना की घोषणा की है। इस मेगा परियोजना में ₹22,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इसका उद्घाटन 16 मई 2025 को किया जाएगा। यह परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सशक्त बनाने में एक मील का पत्थर होगी। (Click here to read article)
- औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वैश्विक निवेश फर्म ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत राज्य में रणनीतिक स्थानों पर 10 से अधिक लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाएगा। यह परियोजना ₹5,127 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के साथ की जा रही है और इससे लगभग 27,510 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होने की संभावना है। (Click here to read article)
- जम्मू और कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने श्रीनगर में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटित किया। यह पहल नदी आधारित संपर्क के उपयोग के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और पर्यावरणीय पर्यटन (इको-टूरिज्म) को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। (Click here to read article)
- पर्यावरणीय स्थिरता और नियंत्रित निर्माण गतिविधियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत (m-sand) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति को मंजूरी दी है। 13 मई 2025 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी और अर्ध-सरकारी निर्माण परियोजनाओं में m-sand का उपयोग अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य नदी रेत के अत्यधिक दोहन को रोकना और स्थायी निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देना है। (Click here to read article)
- भारत के सशस्त्र बलों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राज्य भर में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित सक्रिय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए पूर्ण संपत्ति कर छूट की घोषणा की। यह कदम केवल सेवानिवृत्त सैनिकों या सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लोगों तक सीमित पहले के लाभ का विस्तार है, और अब यह सभी सक्रिय कर्मियों पर लागू होता है, चाहे उनकी वर्तमान पोस्टिंग कहीं भी हो। (Click here to read article)
- स्थानीय शिल्प और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजना "एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)" के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है, जिससे अब राज्य के 75 जिलों में कुल 74 उत्पाद सूचीबद्ध हो गए हैं। यह विस्तार कारीगरों को सशक्त बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। (Click here to read article)

- पारंपरिक पुलिसिंग से सामुदायिक सशक्तिकरण की सराहनीय दिशा में कदम बढ़ाते हुए, दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है – 'नई दिशा – शिक्षा की ओर लौटता मार्ग', जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करना है। यह पहल एनजीओ और स्कूलों के सहयोग से सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने का प्रयास है। (Click here to read article)
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल उत्पादन इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया। ₹300 करोड़ के निवेश से निर्मित इस इकाई का उद्देश्य हर वर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण करना है। यह परियोजना क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। (Click here to read article)

International Affairs

- नेपाल के लांगटांग में स्थित याला ग्लेशियर, जो कभी हिंदू कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र में ग्लेशियोलॉजिकल प्रशिक्षण और क्रायोस्फीयर अनुसंधान का एक अहम केंद्र था, को अब आधिकारिक रूप से "मृत" घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा 12 मई 2025 को की गई, जब वैज्ञानिकों, स्थानीय समुदायों और भिक्षुओं ने मिलकर एक भावुक स्मृति समारोह आयोजित किया। यह घटना ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों को उजागर करती है, जिनका दक्षिण एशिया की जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। (Click here to read article)
- डेनमार्क के कैस्सो (Kasso) में 3 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटित किया गया। यह परियोजना European Energy और जापान की Mitsui द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। संयंत्र प्रति वर्ष 42,000 मीट्रिक टन ई-मेथनॉल का उत्पादन करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और बायोगैस संयंत्रों व अपशिष्ट जलाने से प्राप्त CO_2 का उपयोग होगा। (Click here to read article)
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद, सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय अमेरिका की सीरिया नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जिसका उद्देश्य वर्षों के संघर्ष, गृहयुद्ध और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बाद सीरिया के संक्रमणकालीन सरकार को समर्थन देना और स्थायित्व व शांति की राह को प्रशस्त करना है। (Click here to read article)
- अमेरिका और सऊदी अरब ने 142 बिलियन डॉलर (12.1 लाख करोड़ रुपए) का रक्षा समझौता किया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मई 2025 की रियाद यात्रा के दौरान संपन्न हुआ। व्हाइट हाउस ने इसे अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करार दिया है, जो दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करता है। (Click here to read article)
- वैश्विक आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने अपने लंबे समय से चले आ रहे व्यापार युद्ध में 90-दिवसीय संघर्ष विराम के तहत पारस्परिक टैरिफ में 115% की कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है। जिनेवा में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीनी उप प्रधानमंत्री हे लाइफ़ेंग के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद अंतिम रूप दिया गया यह सौदा दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। (Click here to read article)
- भूटान की रॉयल सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में डिजिटल नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मई 2025 में Binance Pay और DK Bank के साथ साझेदारी में एक क्रिप्टोकरेंसी-आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की है। इस पहल के साथ भूटान पहला संप्रभु देश बन गया है जिसने आधिकारिक रूप से अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान को शामिल किया है। यह प्रणाली वैश्विक पर्यटकों को एक सहज, नकद-मुक्त अनुभव प्रदान करती है और ग्रामीण भूटान में वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहित करती है। (Click here to read article)
- भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है, जिसका 11वां दौर 12 मई 2025 से ब्रसेल्स में शुरू हुआ है। यह दौर समझौते के अंतरिम चरण को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो दो-चरणीय समझौता ढांचे का हिस्सा है और वर्ष के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल भारत की व्यापारिक कूटनीति में हालिया प्रगति के बाद आई है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ FTA लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। (Click here to read article)

Agreements/MoUs Signed

- एडवांस्ड टेलीकॉम सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार के Centre for Development of Telematics (C-DOT) ने Synergy Quantum India के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य ड्रोन-आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) तकनीकों का विकास करना है। यह सहयोग 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना के तहत भारत की क्वांटम-सिक्योर कम्युनिकेशन क्षमताओं को मज़बूती देने की दिशा में कार्य करेगा। (Click here to read article)
- जल संसाधनों की सुरक्षा और अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने 10 मई, 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों राज्यों के चयनित जिलों, विशेष रूप से विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश क्षेत्रों में जल संकट को कम करना और सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना है। (Click here to read article)

Books and Authors

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित आत्मकथा 'जनता की कहानी – मेरी आत्मकथा' का विमोचन नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में एक विशेष समारोह में किया। यह कार्यक्रम 9 मई 2025 को आयोजित हुआ और इसमें भावनात्मक श्रद्धांजलियाँ, राजनीतिक सौहार्द, तथा जन सेवा और सामाजिक कल्याण के प्रति समर्पित जीवन पर चर्चा हुई। (Click here to read article)
- नागालैंड सरकार ने "Transforming Lives" नामक एक कॉफी टेबल बुक जारी की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत राज्य में हुए परिवर्तन और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। यह प्रकाशन शहरी विकास, सस्ते आवास और सामुदायिक सशक्तिकरण से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को उजागर करता है। (Click here to read article)

Banking/Economy/Business News

- चीन की वित्तीय सेवा कंपनी एंट ग्रुप ने अपनी सहयोगी कंपनी Antfin (Netherlands) Holding BV के माध्यम से भारतीय फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Paytm की मूल कंपनी) में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की है। यह बिक्री भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर बल्क डील के माध्यम से की जाएगी। बिक्री की न्यूनतम कीमत ₹809.75 प्रति शेयर तय की गई है, जो कि एनएसई पर पेटीएम के पिछले बंद मूल्य ₹866.05 से लगभग 6.5% कम है। (Click here to read article)
- कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025–26 (FY26) के दौरान भारत में मुद्रास्फीति (Inflation) लक्ष्य के अनुरूप रहने की उम्मीद है। उन्होंने 7 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) की बैठक के दौरान यह बात कही। मल्होत्रा ने बताया कि वर्तमान में मुद्रास्फीति को कम करने वाली शक्तियाँ (Disinflationary forces), मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले जोखिमों की तुलना में अधिक प्रभावी हैं, जिससे विकास को समर्थन देने के लिए मौद्रिक नीति में ढील (Monetary easing) की गुंजाइश बनती है। (Click here to read article)
- भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अप्रैल 2025 के लिए संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का पहला मासिक बुलेटिन जारी किया है। यह नया प्रारूप भारत के श्रम डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) ढांचे के तहत उच्च आवृत्ति, ग्रामीण और शहरी रोजगार-बेरोजगारी संकेतक प्रदान करता है। (Click here to read article)
- भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रतिबद्धताएं अप्रैल 2025 में बढ़कर 6.8 बिलियन डॉलर हो गईं, जो अप्रैल 2024 में दर्ज की गई राशि से लगभग दोगुनी है, जो भारतीय उद्यमों द्वारा वैश्विक विस्तार में मजबूत निवेशक विश्वास को दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह तीव्र वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब भारतीय कंपनियां अपनी विदेशी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश, ऋण और गारंटी के माध्यम से वैश्विक अवसरों का आक्रामक तरीके से लाभ उठा रही हैं। (Click here to read article)
- भारत में अप्रैल 2025 के लिए प्रमुख मुद्रास्फीति दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है, जो एक सकारात्मक आर्थिक संकेत है। अब यह घटकर 3.16% पर आ गई है — जो जुलाई 2019 के बाद सबसे कम है। इस गिरावट का मुख्य कारण सब्जियों, दालों और फलों जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज कमी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) के आंकड़े उपभोक्ताओं और नीति निर्माताओं दोनों के लिए उत्साहजनक संकेत देते हैं। (Click here to read article)
- भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में कोयले के आयात में 9.2% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में है। कुल कोयला आयात 220.3 मिलियन टन (MT) रहा, जो कि 2023–24 में 242.6 MT था। इस गिरावट के परिणामस्वरूप भारत को $6.93 बिलियन (₹53,137.82 करोड़) की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। यह उपलब्धि घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की रणनीतिक पहलों जैसे कॉमर्शियल कोल माइनिंग और मिशन कोकिंग कोल का प्रत्यक्ष परिणाम है। (Click here to read article)
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी निवेश पोर्टफोलियो को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ISARC) में अपनी पूरी हिस्सेदारी ₹34.04 करोड़ में बेचने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बैंक की मुख्य बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और गैर-प्रमुख निवेशों से बाहर निकलने की रणनीति के अनुरूप है। (Click here to read article)
- भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक कैनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। बैंक का शुद्ध लाभ 33.19% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹5,004 करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में ₹3,757.23 करोड़ था। यह परिणाम बैंक की बेहतर संचालन दक्षता और मजबूत ऋण वृद्धि को दर्शाते हैं, हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर थोड़ा दबाव देखा गया। (Click here to read article)
- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सीमा-पार डील के रूप में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और सात निजी बैंकों ने मिलकर यस बैंक में अपनी 20% हिस्सेदारी जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) को ₹13,482 करोड़ में बेच दी है। यह रणनीतिक लेनदेन न केवल भारतीय बैंकिंग में वैश्विक रुचि को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि 2020 के संकट के बाद से यस बैंक ने मजबूत पुनरुत्थान किया है। (Click here to read article)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और उधारकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। RBI (डिजिटल लेंडिंग) दिशानिर्देश, 2025 के तहत सभी विनियमित संस्थाओं (REs) को अपने डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLAs) का विवरण RBI के नए केंद्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) पोर्टल पर 13 मई 2025 से अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य अधिक भरोसेमंद उधारी वातावरण बनाना और अनियमित ऐप्स व अनुचित व्यवहार से जुड़े जोखिमों को कम करना है। (Click here to read article)

Appointments/Resignations

- भारत ने 1995 बैच के अनुभवी भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन साम्राज्य में अगला राजदूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति स्वीडन के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है – जो स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख भागीदार है। (Click here to read article)
- हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज़ (HPE) ने 15 मई 2025 को भारत के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (SVP) और मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) के रूप में भावना अग्रवाल की नियुक्ति की घोषणा की है। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है, जैसा कि कंपनी द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया। भावना अग्रवाल सीधे हेइको मेयर, कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य बिक्री अधिकारी, को रिपोर्ट करेंगी और भारत में HPE के व्यापारिक रणनीति और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी। (Click here to read article)
- हरवंश चावला, के.आर. चावला एंड कंपनी एडवोकेट्स के संस्थापक और प्रबंध भागीदार, को BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BRICS CCI) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह नेतृत्व परिवर्तन BRICS देशों—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—के बीच मज़बूत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की चैंबर की नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कॉर्पोरेट कानून और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, चावला से इस समूह में नवाचार-आधारित सहयोग और सतत विकास को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। (Click here to read article)
- न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई 2025, बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की। यह समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति रही, जिसने भारत के न्यायिक और संवैधानिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। (Click here to read article)
- केरल कैडर के सेवानिवृत्त 1985 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रक्षा सुधारों और डिजिटल गवर्नेंस में व्यापक अनुभव के साथ, उनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और 29 अप्रैल, 2025 को प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई जगह को भरेंगे। (Click here to read article)

Defence News

- अर्जुन Mk1A भारत में स्वदेशी रूप से विकसित टैंक है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह अर्जुन Mk1 का उन्नत संस्करण है और इसमें वर्षों के डिजाइन अनुभव, विकास और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया को सम्मिलित किया गया है। इसका डिज़ाइन क्रू की सुरक्षा, भारी कवच और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर केंद्रित है। (Click here to read article)
- तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने कानपुर स्थित अपनी प्रयोगशाला डीएमएसआरडीई के माध्यम से समुद्री जल विलवणीकरण के लिए एक उच्च दबाव वाली नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह नवाचार भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है और एक अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) पर प्रारंभिक तकनीकी परीक्षणों को पहले ही पास कर चुका है। (Click here to read article)

Awards and Recognitions

- ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हुनग्रिया को 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज़ (World Food Prize) से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Biological Nitrogen Fixation) पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए दिया गया है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया से फसलों की वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है। उनके शोध ने ब्राजील को दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बनने में मदद की है और पर्यावरण-संवेदनशील खेती को बढ़ावा दिया है। (Click here to read article)
- भारत की बाल न्याय के लिए लड़ाई को ऐतिहासिक वैश्विक मान्यता मिली है, जब प्रसिद्ध वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिभु को विश्व विधि संघ (World Jurist Association) द्वारा "मेडल ऑफ ऑनर" से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया। भुवन रिभु यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। (Click here to read article)

Summits and Conferences News

- मुंबई में 13 मई 2025 को पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय और राज्य स्तर के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही, जिनमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्रियों, अधिकारियों और उपयोगिता क्षेत्र के नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना था। प्रमुख मुद्दों में स्मार्ट मीटरिंग, एटीएंडसी (AT&C) हानियों में कमी, ट्रांसमिशन क्षमता में वृद्धि, और ग्रीन एनर्जी ज़ोन की स्थापना शामिल थे ताकि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। (Click here to read article)

- GAAD के अवसर पर DEPwD द्वारा आयोजित समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल पहुंच और समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए हितधारकों को एक साथ लाता है। पैनल चर्चाओं, साझेदारियों, AI चैटबॉट के लॉन्च और एक नए सुलभता-केंद्रित पाठ्यक्रम के माध्यम से, शिखर सम्मेलन तकनीकी समानता के लिए भारत के प्रयास को उजागर करता है। यह सहयोगात्मक प्रयास डिजिटल रूप से समावेशी भविष्य के लिए देश के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। (Click here to read article)

Ranks and Reports

- भारत ने वैश्विक स्तर पर 6G तकनीकों के लिए पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष छह देशों में स्थान हासिल किया है, यह घोषणा केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने की। वे 14 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित "भारत 6G 2025 – तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी" को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने भारत की मजबूत शोध प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय सहयोगों को 6G में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक प्रमुख कदम बताया। (Click here to read article)

Sports News

- भारतीय शतरंज के महारथी ग्रैंडमास्टर आर. प्रग्गनानंद ने रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित अपने पहले ग्रैंड शतरंज टूर टूर्नामेंट – सुपरबेट क्लासिक 2025 को जीतकर अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वे मैक्सिम वचियर-लाग्रेव और अलीरेजा फिरौजा सहित शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ियों के खिलाफ एक तनावपूर्ण टाईब्रेक लड़ाई के बाद विजयी हुए, जिसने वैश्विक मंच पर भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। (Click here to read article)
- मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने 16 मई, 2025 को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया, जिसमें टेस्ट और टी20 क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेट के दिग्गज को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में अजीत वाडेकर और शरद पवार के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन भी हुआ, जो भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट प्रशासन में उनके अमूल्य योगदान को याद करते हैं। (Click here to read article)
- फीफा ने आधिकारिक तौर पर कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ (FECOFOOT) पर लगाया गया निलंबन हटा लिया है, जिससे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के आरोपों के कारण तीन महीने से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। FECOFOOT और कांगो के खेल मंत्रालय के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण लगाए गए इस प्रतिबंध ने राष्ट्रीय फुटबॉल संचालन को बाधित कर दिया था और महासंघ के मुख्यालय सहित प्रमुख खेल सुविधाओं को बंद कर दिया था। (Click here to read article)
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल 2023-25 के विजेताओं के लिए रिकॉर्ड 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹30 करोड़) की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 जून 2025 से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। यह पुरस्कार राशि अब तक की सबसे बड़ी है और पिछले संस्करणों में दी गई राशि से दोगुनी से भी अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ICC टेस्ट क्रिकेट के गौरव को आधुनिक युग में और ऊंचा उठाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। (Click here to read article)
- भारत ने अपना 86वाँ शतरंज ग्रैंडमास्टर हासिल कर लिया है, चेन्नई के 19 वर्षीय श्रीहरि एलआर ने यूएई के अल-ऐन में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ, भारत एक उभरती हुई शतरंज महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। (Click here to read article)
- बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह सम्मान उन्हें ज़िम्बाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए दिया गया। यह मिराज का पहला अवसर है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता है, और वह यह सम्मान पाने वाले केवल तीसरे बांग्लादेशी क्रिकेटर बने हैं। उनसे पहले मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन को यह उपलब्धि मिली थी। (Click here to read article)
- भारत ने शंघाई में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर वापसी करते हुए अपना 18वां वर्ल्ड कप पदक जीता, जबकि युवा प्रतिभा पार्थ सालुंखे ने सीनियर स्तर पर पहला कांस्य पदक जीतकर भारत की बढ़ती ताकत और गहराई को प्रदर्शित किया। (Click here to read article)
- धर्मशाला में 8 मई 2025 को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चल रहे मैच के दौरान सुरक्षा कारणों से IPL 2025 को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। अब, BCCI ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के बाद टूर्नामेंट के पुनः आरंभ की घोषणा की है। (Click here to read article)
- भारत की शीर्ष तीरंदाज़ दीपिका कुमारी ने 11 मई 2025 को शंघाई में आयोजित तीरंदाज़ी विश्व कप स्टेज-2 में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। विश्व नंबर 1 लिम सिह्योन से सेमीफाइनल में हार के बाद, दीपिका ने जबरदस्त धैर्य और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए कोरिया की कांग चे यंग को कांस्य पदक मुकाबले में 7-3 से हराया। इस जीत के साथ भारत का कुल पदक संग्रह छह हो गया, जो वैश्विक मंच पर भारतीय तीरंदाज़ी की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। (Click here to read article)
- अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने आधिकारिक रूप से शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया है, यह कहते हुए कि यह इस्लामी कानून के अनुरूप नहीं है। यह घोषणा 12 मई 2025 को की गई और यह तालिबान द्वारा अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों पर लगाए जा रहे कठोर प्रतिबंधों का हिस्सा है। यह प्रतिबंध फिलहाल अस्थायी है और धार्मिक अधिकारियों द्वारा समीक्षा लंबित है, लेकिन इसका प्रभाव पहले ही काबुल और अन्य क्षेत्रों में दिखने लगा है। (Click here to read article)

Science and Technology News

- भारत 2026 में निर्धारित अपने पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन, 'समुद्रयान' के प्रक्षेपण के साथ समुद्री अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार है। स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी वाहन, मत्स्य 6000 का उपयोग करते हुए, इस मिशन का उद्देश्य 6,000 मीटर तक की समुद्री गहराई का अन्वेषण करना है, जिससे समुद्री जैव विविधता और संसाधन क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सके। (Click here to read article)
- भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment & Employment) नीति के तहत एक ऐतिहासिक पहल की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर जैविक प्रयोग करेगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थायित्व का अध्ययन करना है। यह प्रयोग AXIOM-4 मिशन के तहत किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी चालक दल के सदस्य होंगे। (Click here to read article)
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 (11 मई) के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार ने सीमेंट क्षेत्र के लिए देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन (CCU) टेस्टबेड क्लस्टर लॉन्च किया। यह पहल Public-Private Partnership (PPP) मॉडल पर आधारित है और नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है। (Click here to read article)
- भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस समझौते को औपचारिक रूप से एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया, जिसे आर्यभट्ट प्रेक्षणीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान (ARIES), नैनीताल और इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (IRDE), देहरादून के बीच हस्ताक्षरित किया गया। (Click here to read article)
- एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि में, मुख्यतः चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज़ के शोधकर्ताओं ने एशियाई खेती योग्य धान (Oryza sativa L.) का पहला पैनजीनोम (Pangenome) तैयार किया है। 144 प्रकार की धान की किस्मों—जंगली और खेती योग्य—के जीनोम को अनुक्रमित (sequence) करके, इस शोध ने एक व्यापक आनुवंशिक मानचित्र प्रदान किया है, जो धान की नस्लों को जलवायु-संवेदनशील, अधिक उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी बनाने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। यह खोज वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित फसलों की विफलता से लड़ने में एक मील का पत्थर है। (Click here to read article)
- बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप Sarvam AI ने अपना नवीनतम टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS) मॉडल 'Bulbul-v2' लॉन्च किया है, जिसे विशेष रूप से भारत की विविध भाषाई पहचान को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह मॉडल 11 भारतीय भाषाओं में प्राकृतिक, मानवीय जैसी आवाज़ें और प्रामाणिक क्षेत्रीय उच्चारण प्रदान करता है, जिससे यह बिज़नेस, ब्रांड और डेवलपर्स के लिए एक प्रभावशाली उपकरण बनता है जो भारतीय दर्शकों के लिए अनुकूल आवाज़ों की तलाश में हैं। (Click here to read article)

Important Days News

- राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डेंगू बुखार की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह एक मच्छर जनित विषाणुजनित रोग है जो खासकर मानसून के मौसम में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। यह दिवस केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और जनजागरूकता, समय पर निदान, सामुदायिक भागीदारी और सशक्त स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से डेंगू की बीमारी और मृत्यु दर को कम करने पर बल देता है। (Click here to read article)
- अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जो हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है, एक विशेष अवसर है जिसे दुनिया भर में परिवारों की समाज में केंद्रीय भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य एक वैश्विक मंच प्रदान करना है जहाँ आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में परिवारों को दरपेश विभिन्न चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, साथ ही ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके जो पारिवारिक संबंधों को मजबूत करें और उनके कल्याण व विकास को समर्थन दें। (Click here to read article)
- हर वर्ष 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस (IND) मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह दिवस स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास में नर्सों की अहम भूमिका को पहचानता है। (Click here to read article)
- भारत ने 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया, जो पोखरण में 1998 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है, साथ ही यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती ताकत को भी मान्यता देता है। इस वर्ष का विषय है – "नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना", जो पर्यावरण-अनुकूल, स्वदेशी और अभिनव तकनीकी समाधानों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। (Click here to read article)

Obituaries News

- पूर्व उरुग्वे राष्ट्रपति जोस मुजिका, जिन्हें उनकी सादगीपूर्ण जीवनशैली के कारण "दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति" के रूप में जाना जाता था, का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अन्ननलिकाशोथ (oesophageal cancer) से पीड़ित थे। मुजिका का असाधारण जीवन – एक गुरिल्ला योद्धा से लेकर प्रगतिशील राष्ट्र प्रमुख बनने तक – सादगी, सामाजिक सुधारों और मानव गरिमा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व ने उरुग्वे को ऐतिहासिक सुधारों की ओर अग्रसर किया और उनके सरल जीवन और गहन राजनीतिक दृष्टिकोण ने दुनियाभर के लोगों को प्रेरित किया। (Click here to read article)
- पद्म श्री से सम्मानित और अग्रणी मत्स्य वैज्ञानिक डॉ. सुब्बन्ना अय्यप्पन का 10 मई 2025 को कर्नाटक के श्रीरंगपट्टण के पास कावेरी नदी में मृत अवस्था में शव मिला। भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन (नीली क्रांति) के प्रमुख वास्तुकार माने जाने वाले डॉ. अय्यप्पन की रहस्यमयी मृत्यु ने संस्थागत भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच न्यायालय की निगरानी में CBI जांच की मांग को जन्म दिया है। (Click here to read article)

Miscellaneous News

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अंडमान सागर के ऊपर एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) की पहचान की है, जो 16 से 22 मई के बीच एक निम्न-दाब क्षेत्र (low-pressure system) में विकसित हो सकता है। यदि तीव्रता बढ़ती है, तो यह 23 से 28 मई के बीच एक चक्रवातीय तूफान (cyclonic storm) का रूप ले सकता है, जिसे चक्रवात शक्ति नाम दिया जाएगा (यह नाम श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित किया गया है)। (Click here to read article)

Static Takeaways

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
		राज्य/देश
1	दिल्ली	**एल. गवर्नर - विनय सक्सैना** **सीएम - रेखा गुप्ता**
2	महाराष्ट्र	**राज्यपाल - सी. पी. राधाकृष्णन** **मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस**
3	आंध्र प्रदेश	**राज्यपाल - अब्दुल नजीर** **सीएम - चंद्रबाबू नायडू**
4	उतार प्रदेश।	**राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल** **सीएम - योगी आदित्यनाथ**
5	उत्तराखंड	**राज्यपाल-गुरमित सिंह** **सीएम-पुष्कर धामी**
6	जम्मू और कश्मीर	**उपराज्यपाल-मनोज सिन्हा** **मुख्यमंत्री - उमर अब्दुल्ला**
		राज्य/देश
7	यूएसए	**राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प** **राजधानी - वाशिंगटन डी.सी.** **मुद्रा - USD**
8	चीन	**राष्ट्रपति - शी जिनपिंग** **राजधानी - बीजिंग** **मुद्रा - युआन**
9	भूटान	**पीएम- शेरिंग टोबगे** **राजधानी - थिंपू** **मुद्रा - नगुल्ट्रम**
10	जापान	**राष्ट्रपति - शिगेरू इशिबा** **राजधानी - टोक्यो** **मुद्रा - येन**
11	कनाडा	**राष्ट्रपति - मार्क कार्नी** **राजधानी - ओटावा** **मुद्रा - कनाडाई डॉलर**

क्रमांक	स्थैतिक नाम	स्थैतिक विवरण
12	सऊदी अरब	**राष्ट्रपति - मोहम्मद बिन सलमान** **राजधानी - जेद्दा** **मुद्रा - सऊदी रियाल**
13	होंडुरस	**राष्ट्रपति - शियोमारा कास्त्रो** **राजधानी - तेगुसिगाल्पा** **मुद्रा - लेम्पिरा**
		संगठन
14	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया	**सीईओ - शांतनु मित्रा**
15	यस बैंक	**एमडी - प्रशांत कुमार** **मुख्यालय - मुंबई**
16	आरबीआई	**राज्यपाल - संजय मल्होत्रा**
17	पीएनबी	**एमडी - अशोक चंद्रा** **मुख्यालय - नई दिल्ली**
18	यूनियन बैंक	**एमडी - मणिमेखलाई** **मुख्यालय - मुंबई**
19	केनरा बैंक	**एमडी - सत्यनारायण राजू** **मुख्यालय - बेंगलुरु**
20	यूपीएससी	अध्यक्ष - अजय कुमार
21	सुप्रीम कोर्ट	CJI - जस्टिस गवई
22	इसरो	अध्यक्ष - वी नारायणन